राशन-किरासन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबों से दूर होते शिक्षा व स्वास्थ्य और भुखमरी इत्यादि के खिलाफ संघर्ष तेज करें

साथियों,

बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन जनता के मुद्दे फिर भी गायब हैं। वोट के लिए प्रचार में लाखों नहीं करोड़ों रूपये खर्च किये जा रह हैं, लेकिन जनता के मूलभूत मांगों व अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। सभी दल दूसरे दलों पर तीखा हमला करते हुए अपने आप को जनता का हितैषी साबित करने में लगे हैं लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि पूंजीपति मालामाल और जनता कंगाल क्यों होती जा रही है। चंद हफ्तों तक शोरगुल और जनता की सेवा के दिखावे के बाद चुनाव संपन्न होते ही वोट लेने वाले अपने-अपने घरों को चले जाएंगे। जनता की समस्यायें वहीं की वहीं बनी रहेंगी। पिछले 70 सालों से यही तो हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदले बिना कोई भी सरकार जनता के लिए नही होती है।

सवाल है, पूंजीवादी व्यवस्था की पहचान क्या है? यही कि संपत्ति चंद बड़े पूंजीपतियों के पास जमा होता जाता है और दूसरी ओर गरीबी और सर्वहाराओं का महासमुद्र बनता जाता है। पूंजीवाद में किसी भी दल की सरकार इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती है, उल्टे सरकार इसे संपन्न करने हेतु बनती है। सरकार और व्यवस्था का यही संबंध है जिसके आधार पर पूंजीपति वर्ग की लूट चलती रहती है। आम जनता (मजदूर, मेहनतकश, छोटे-मंझोले किसान, छोटे दुकानदार तथा व्यवसायी आदि) सभी इसमें पीसते हैं। पूंजीवाद में भ्रष्टाचार का आलम आम बात है। रेलवे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज से लेकर बीएसएनएल, बीमा, कोयला, तेल जैसी समस्त सरकारी कंपनियों को सरकार अत्यंत सस्ते दामों पर पूजीपतियों को बेचती जा रह है। शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भी सरकार पूंजीपतियों को सौंपती जा रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भी सरकार पूंजीपतियों को सौंपती जा रही है। मजदूरों के हितों में काम करने वाले सारे कानूनों को सरकार ने खत्म कर दिया है। महंगाई चरम पर है। सभी प्राकृतिक साधन व संसाधन भी सरकार निजी पूंजीपतियों को सौंपती जा रही है।

जरा सोंचिये, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हमारे देश मे 21.92 % आबादी यानी लगभग 30 करोड़ लाग गरीबी रेखा के भी नीचे जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा लोग गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा और बदतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जी रहे हैं । गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और बढ़ती जा रही है, एक तरफ उत्पादन क्षमता चरम पर है, तो दूसरी तरफ अभाव और लाचारी और गहराते जा रहे हैं। कोरोना संकट के पूर्व ही देश मे बेरोजगारी का अब तक का सबसे ज्यादा दर था। लाखों टन अनाज होने के बावजूद भी लगभग 35 करोड़ लोग भुखमरी से जूझते हैं। लाकडाउन के बाद तो जीवन और नारकीय बन गया है। महामारी के दौर में इतने दिनों बाद भी इलाज की कोई सही व्यवस्था नही है । दूसरी तरफ, अंबानी-अडानी जैसे पूंजीपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। करोडों लोगो का घर उजड़ गया, पर पूंजीपति लगातार मालमाल हो रहे हैं। आवाज उठाने पर लोगों को पुलिस की लाठी का शिकार होना पड़ रहा है । वर्तमान में लोगो के पास न तो खाने, इलाज के लिए पैसा है और न ही इसकी व्यवस्था के लिए कोई काम ही मिल रहा है। नया काम मिलना तो दूर, पुराने कामो में भी छटनी हो रही है। ऐसे में सरकारें मरती हुई जनता को और लूटने के लिये नए नए कानून ला रही है। नये श्रम कानून (श्रम कोड), नई शिक्षा नीति, न्या कृषि सुधार कानून आदि लेकर सरकार आई है जिससे गरीब व मेहनतकश जनता से सब कुछ छीन जाएगा।

सवाल है, क्या किया जाए? इस प्रश्न पर जनता न सोंचे इसी लिए के लिए हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति तेज की जा रही है। उसी तरह पाकिस्तान,चीन,जाति तथा धर्म, मंदिर-मस्जिद के मुद्दों को जनता के बीच परोसा जा रहा है। इससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर काले कानूनो के जरिये जनता के सवालों को उठाने वालों को जेलों में डालने की साजिश चल रही है। तो आखिर समाधान क्या है ?

इसका अंतिम समाधान तो है पूंजीवाद को हटाना और नई व्यवस्था बनाना, लेकिन उसके पहले हमें अपने मुद्दों पर संघर्ष करना होगा। आज तक राशन,किरासन की समुचित व्यवस्था नही हो सकी है। जिनके पास राशन कार्ड है भी आए दिन उनको खराब राशन, कम राशन व अन्य भी तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में हजारों घरों तक पहुंचने का कोई ठीक रास्ता नही है, शिक्षा के लिए न तो ढंग का विद्यालय है, न ही पर्याप्त संख्या में है, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के लिए तो दूर तक कोई चर्चा भी नही है। कोरोना जैसे महामारी देखने के बावजूद आज तक चिकित्सा के लिए ढंग की कोई कोई व्यवस्था नहीं है। जलजमाव से पूरा इलाका खतरे में डूबा रहता है। परंतु बड़े नेताओं की तो छोड़िए स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए भी आम गरीब जनता का दर्द समझना और उसके लिए काम करना दोयम दर्जे की बात मालूम पड़ती है, जबकि हम जानते हैं कि सरकार और पूरे तंत्र में एक अदना कर्मचारी, एक स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर प्रधानमंत्री तक का खर्च जनता के कोष से ही होता है।

इसीलिए हमारी अपील है कि आइए, अपनी मूलभूत समस्याओं के मुद्दे पर संघर्ष को तेज करें। आइए, हम एकता बनाकर अपने हक़ अधिकारों के लिए मुखर होकर विरोध करें। स्थानीय नेताओं,अधिकारियों और प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी का बोध कराएं। और ये संघर्ष अलगाव में रहकर नही हो सकता। इसलिए आइए मजदूर मेहनतकश वर्ग की एकता बनायें और इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़कर हम अपने हक को सुनिश्चित करें।

संपतचक प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी निम्नलिखित मांगे हैं

1. **राशन वितरण में व्याप्त धांधली व राशन की खराब गुणवत्ता को लेकर तुरंत संज्ञान लिया जाए और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए व गुणवत्तापूर्ण राशन मुहैया कराया जाए।**
2. **आवेदन कर चुके लोगों एवं सभी जरूरतमंदों को जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। उपलब्ध न हो पाने तक सभी को सार्वभौमिक तरीके से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए।**
3. **काम नहीं मिल पाने की स्थिति में एवं लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों एवं उनके परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, नहीं मिल पाने तक 15,000 प्रति माह बेरोजारी भत्ते के रूप में देना सुनिश्चित किया जाए।**
4. **क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र का जल्द निर्माण किया जाए।**
5. **हमेशा बने रहने वाले खतरनाक जलजमाव का समाधान किया जाए तथा गली और सड़क जल्द से जल्द बनवाए जाएं और उनकी मरम्मत की जाए**

निवेदक

सर्वहारा जन मोर्चा

(महिला कामगार संघर्ष यूनियन, आईएफटीयू - सर्वहारा, असंगठित भवन व निर्माण मजदूर यूनियन)

संपर्क:
(9199748982, 9708868740)